



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 2006/1 पौष, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 नवम्बर, 2006

संख्या गृह-बी(बी) 2-4/2004-सुज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्त) अधिनियम, 2003 (2003 का 10) की धारा 4 की उप-धारा (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 233, 234 और अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त उन्हें सशक्त बनाने के लिए अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 2004 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 15 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 2004 के नियम 15 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम (3) और (4) जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

“(3) सेवा का सदस्य, सक्षम प्राधिकारी को, लिखित रूप में कम से कम तीन मास का नोटिस देकर (तामील कर) सेवा से समय पूर्व सेवा निवृत्ति की चेष्टा कर सकेगा :

परन्तु सेवा का कोई भी सदस्य इस उप-नियम के अधीन समय पूर्व सेवा निवृत्ति की चेष्टा करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने न्यूनतम 30 वर्ष की सेवा पूर्ण न की हो या 50 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो ।

4. सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में कम से कम तीन मास के नोटिस की प्राप्ति पर किसी अधिकारी को, जिसका अभिलेख रिकार्ड उक्त प्राधिकारी द्वारा संतोषप्रद पाया गया है, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर या 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या तत्पश्चात् सेवा निवृत्त होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा । सेवा के किसी सदस्य को, जिसे इस उपबन्ध के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया गया है, पेंशन के प्रयोजन हेतु अर्हता सेवा के रूप में पांच वर्ष की अतिरिक्त सेवा की प्रसुविधा इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि अधिकारी की कुल अर्हता सेवा किसी भी दशा में 33 वर्ष से अधिक न हो जाए और उसे अधिवर्षिता की तारीख से परे न ले जाए :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को, जो निलम्बित है या जिसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित है अथवा अनुध्यात है या जिसके विरुद्ध कोई सतर्कता मामला विभागीय जांच चल रही है इस नियम के उप-नियम (3) या उप-नियम (4) के अधीन सेवा निवृत्त होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।”

आदेशानुसार,

एस 0 विजय कुमार,  
प्रधान सचिव ।

## HOME DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 20th November, 2006*

**No. Home-B(B) 2-4/2004-Loose.**—In exercise of the powers conferred by articles 233, 234 and proviso to article 309 of the Constitution of India read with sub-section (i) of section 4 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003 (Act No. 10 of 2003) and all other powers enabling him in this behalf the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the High Court of Himachal Pradesh and Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Judicial Service (IIInd Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. *Amendment of rule-15.*—In rule 15 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, after sub-rule (2), the following sub-rules (3) and (4) shall be added, namely :—

“(3) A member of the service, by serving a notice, in writing of not less than three months to the competent authority, may seek pre-mature retirement from service:

Provided that no member of the service shall be eligible to seek pre-mature retirement under this sub-rule unless he has completed a minimum of 30 years service or has attained the age of 50 years.

(4) The competent authority, on receipt of notice in writing, of not less than three months, may allow an officer whose record is found satisfactory by the said authority to retire on completion of 20 years of service or attaining the age of 50 years or thereafter. Any member of the service who is allowed to retire from service under this provision, shall be given the benefit of five years' Additional service in the form of qualifying service for the purpose of pension subject to the condition that the total qualifying service of the officer does not in any case exceed 33 years and does not take him beyond the date of superannuation:

Provided that no member of the service who is under suspension or against whom any departmental proceeding is pending or contemplated or against whom any vigilance matter/departmental enquiry is going on, shall be permitted to retire either under sub-rule (3) or sub-rule (4) of this rule.”

By order,

Sd/-  
Principal Secretary.

